हॉर्मुज तनाव से तेल कीमतें बेकाबू

ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर के पार

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया

नई दिल्ली, 30 अप्रैल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन तेज कर दी है. हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार पर दिखा. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिससे ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता, तब तक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी. ट्रंप ने इस कदम को ईरान पर दबाव बनाने का सबसे असरदार हथियार बताते हुए कहा कि यह सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो रहा है.

दरअसल, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट का मतलब है—पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर खतरा और कीमतों में बेकाबू उछाल. यही वजह है कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद बाजारों में घबराहट फैल गई और निवेशकों ने तेजी से खरीदारी शुरू कर दी.

रुपया में ऐतिहासिक गिरावट

भारतीय रुपये में हालिया दिनों में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिसने इसे डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. यह गिरावट केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर असर डालने वाला संकेत है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसका सबसे बड़ा कारण मानी जा रही हैं, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसके अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पूंजी निकालना और अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने रुपये पर दबाव और बढ़ा दिया है.

टाटा पावर-केप्पल चेन्नई में कूलिंग सेवा लागू

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल बिजली कंपनी टाटा पावर ने चेन्नई के इनटेलियन पार्क में कूलिंग-एज-ए-सर्विस समाधान लागू करने के लिए केप्पल लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर डिविजन के साथ हाथ मिलाया है.

टाटा पावर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल) के जरिये यह समाधान लागू करेगी. इनटेलियन पार्क का स्वामित्व इंफोपार्क प्रोपर्टीज लिमिटेड के पास है जो टाटा रियलटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीआरआईएल) की इकाई है. यह 25.27 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और गैर-सेज दोनों शामिल हैं. यह तारामणि के आईटी कॉरिडोर में रणनीतिक रूप से स्थित है.

नई अर्थव्यवस्था में बदलनी होगी रणनीति

संरक्षणवाद से 'सावधानी नीति' की ओर रुख

नई दिल्ली, 30 अप्रैल बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच विश्व व्यापार संगठन की भूमिका और प्रासंगिकता को लेकर गंभीर बहस तेज हो गई है.

पूर्व महानिदेशक पास्कल लैमी ने स्पष्ट कहा है कि तेजी से बदल रहे वैश्विक व्यापार ढांचे के अनुरूप डब्ल्यूटीओ को अपने नियमों, प्रक्रियाओं और संस्थागत ढांचे में व्यापक सुधार करना होगा.

नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय चर्चा में लैमी ने कहा कि दुनिया अब पारंपरिक संरक्षणवाद से आगे बढ़कर 'सावधानी आधारित नीति' की ओर बढ़ रही है. इसका मतलब यह है कि देश अब केवल अपने उद्योगों को बचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त व्यापार नियम लागू कर रहे हैं. यह चर्चा चिंतन रिसर्च फाउंडेशन और कट्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें कई प्रमुख नीति विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया.

सत्र की अध्यक्षता करते हुए शशि थरूर ने कहा कि वैश्विक व्यापार इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. देशों के बीच भरोसा घट रहा है और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. ऐसे में डब्ल्यूटीओ को अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, ताकि वह वैश्विक व्यापार को संतुलित और स्थिर बनाए रख सके. वहीं, अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि डब्ल्यूटीओ से हर समस्या के समाधान की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि देशों को अपनी व्यापार नीतियों को अधिक लचीला और परिस्थितियों के अनुसार बनाना चाहिए.

मिडिल ईस्ट तनाव, फेड ने दरें रोकी

ब्याज दर 3.5-3.75% पर बरकरार

नई दिल्ली, 30 अप्रैल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ऊर्जा कीमतों में तेजी के बीच फेडरल रिजर्व (फेड) ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है. फेड ने अपनी बेंचमार्क दर 3.5 से 3.75 प्रतिशत के बीच स्थिर रखी है, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच सतर्क रुख को दर्शाता है.

फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक रोजगार बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के अपने दोहरे लक्ष्य पर फोकस बनाए हुए है, भले ही महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. उन्होंने स्वीकार किया कि मिडिल ईस्ट संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में उछाल आया है, जिससे महंगाई पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

पॉवेल के मुताबिक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है. उपभोक्ता खर्च और कारोबारी निवेश में मजबूती बनी हुई है, हालांकि नौकरी वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है और हाउसिंग सेक्टर अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जल्दबाजी में कोई नीति बदलाव करना उचित नहीं होगा और आगे के फैसले आर्थिक आंकड़ों और जोखिमों को देखते हुए लिए जाएंगे.

ई100 ईंधन नोटिफिकेशन पेट्रोल पर बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, 30 अप्रैल देश में पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और सस्ती, स्वदेशी ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ई100 ईंधन को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों को बढ़ावा दिया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना और घरेलू स्तर पर तैयार वैकल्पिक ईंधन को मुख्यधारा में लाना है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर ई85 और ई100 ईंधन को शामिल करने की योजना है. ई20 कार्यक्रम का अगला चरण माना जा रहा है, ऐसे वाहनों को बढ़ावा मिलेगा जो अधिक इथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं.

चांदी उछली, सोना भी हुआ मजबूत

920 रुपए महंगा हुआ सोना

3,380 रुपए उछली चांदी

नई दिल्ली, 30 अप्रैल घरेलू सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया. आज 30 अप्रैल को सोना 920 रुपये बढ़कर 24 कैरेट में 1,50,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,37,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं चांदी में बड़ी तेजी देखने को मिली और इसका भाव करीब 3,380 रुपये उछलकर 2,41,610 रुपये प्रति किलो हो गया.

अंतरराष्ट्रीय संकेतों और मजबूत मांग के चलते दोनों कीमती धातुओं में यह तेजी देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोना और चांदी दोनों हरे निशान में कारोबार करते दिखे, जिससे बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है.

देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के दाम ऊंचे बने हुए हैं. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,49,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1,37,372 रुपये पर पहुंच गया. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिल रही है. वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर झुकाव सोने-चांदी की कीमतों को समर्थन दे रहा है. आने वाले दिनों में भी इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है.

एआई से अल्फाबेट की कमाई हुई तेज

नई दिल्ली, 30 अप्रैल टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अल्फाबेट इंक ने अपनी ताज़ा तिमाही रिपोर्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाज़ार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है. कंपनी की तेज़ प्रगति के पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती मांग और क्लाउड सेवाओं का विस्तार प्रमुख कारण रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का कुल राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 109.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो उम्मीद से अधिक है.

कंपनी की क्लाउड इकाई (गूगल क्लाउड) ने इस तिमाही में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इसका राजस्व 63 प्रतिशत बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया. यह वृद्धि मुख्य रूप से एंटरप्राइज ग्राहकों द्वारा एआई आधारित सेवाओं को तेजी से अपनाने के कारण हुई है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा कि एंटरप्राइज एआई अब क्लाउड कारोबार का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन गया है.अल्फाबेट ने पहली बार अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टीपीयू चप्स को सीधे ग्राहकों को बेचना शुरू किया है. ये चिप्स एआई कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं और बाज़ार में एनवीडिया के उत्पादों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इस कदम से कंपनी को नए आय स्रोत मिलने की उम्मीद है.

कंपनी ने अपने पूंजीगत खर्च का अनुमान बढ़ाकर 180 से 190 अरब डॉलर कर दिया है, जिससे साफ है कि वह एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है. क्लाउड इकाई का संचालन मुनाफा 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि कुल शुद्ध आय 81 प्रतिशत बढ़कर 62.6 अरब डॉलर हो गई है.

प्रतिस्पर्धा के बीच अमेजन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसी कंपनियों के सामने अल्फाबेट का यह प्रदर्शन दिखाता है कि एआई अब कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार बन चुका है. कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में एआई और क्लाउड तकनीक कंपनी की कमाई का मुख्य स्रोत बनी रहेंगी.

स्मार्ट बाजार का 'फुल पैसा वसूल'

मुंबई 30 अप्रैल. स्मार्ट बाजार का 'फुल पैसा वसूल' इवेंट महीने की शुरुआत में बड़ी बचत का मौका लेकर आया है।

ज्यादातर भारतीय घरों के लिए महीने की शुरुआत वह समय होता है जब घर की सारी जरूरी खरीदारी की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट बाजार ने यह खास इवेंट शुरू किया है, जो 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। यह ग्राहकों के लिए घर का सामान एक साथ खरीदने और ज्यादा बचत करने का सही समय है।

इन 5 दिनों में ग्राहक रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, खाने का तेल और रसोई व घर की दूसरी जरूरतों पर शानदार ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो हर महीने खरीदी जाती हैं और बजट का बड़ा हिस्सा होती हैं। इसका मकसद यह है कि परिवार अपनी जरूरी खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें।

ये ऑफर्स आसान और साफ हैं—कीमतों में सीधी छूट और वैल्यू डील्स के साथ, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो। वे आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी चीज सस्ती है और अपनी जरूरत के अनुसार सही सामान चुन सकते हैं।

एचएफसीएल को चौथी तिमाही में 184 करोड़ रुपये का मुनाफा

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना और रक्षा क्षेत्र की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी एचएफसीएल का समेकित शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 184.45 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले समान तिमाही में उसे 83.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. कंपनी ने गुरुवार को घोषित वित्तीय परिणामों के बारे में कहा है कि यह अब तक उसका सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन है.

शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज

नई दिल्ली, 30 अप्रैल. घरेलू शेयर बाजारों में आज उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई.

प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 582.86 अंकों की गिरावट के साथ 76,913.50 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी-50 भी 180.10 अंक टूटकर 23,997.55 पर आ गया. बाजार की इस कमजोरी के पीछे वैश्विक संकेतों की नकारात्मकता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और प्रमुख सेक्टरों में दबाव को मुख्य कारण माना जा रहा है. आईटी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में खासा दबाव देखा गया, जिससे बाजार पर व्यापक असर पड़ा. वहीं, कुछ चुनिंदा एफएमसीजी और फार्मा शेयरों ने मामूली सहारा देने की कोशिश की, लेकिन यह गिरावट को थामने के लिए पर्याप्त नहीं रहा. विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के रुख को सतर्क बना दिया है.

समाचार विशेष

क्या अखिलेश का खेल बिगाड़ेंगे चंद्रशेखर?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनाव को देखते हुए नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समंदाय मे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2 जून 2026 से पूरे प्रदेश में यात्रा शुरु करेंगे.

प्रदेशव्यापी यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं. यात्रा पर जानकारी देते हुए एएसपी के नेताओं ने बताया कि इस यात्रा के जरिए चंद्रशेखर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे. उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है.

प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ राज्य में पार्टी का विस्तार करने की उनकी महत्वाकांक्षा ने सपा और कांग्रेस में हलचल की स्थिति पैदा कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में कुछ सपा सांसदों ने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से चंद्रशेखर के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की थी.

पार्टी सांसदों के इस सुझाव को अखिलेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया था. गौर करने वाली बात ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए का नारा दिया था. पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को ही टारगेट किया था. पार्टी को पीडीए का फायदा भी मिला था. लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था.

सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर ईबीसी उम्मीदवार उतारने की तैयीरी में है. साथ ही पार्टी 50 सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. पार्टी नेताओं के मुताबिक यह चुनाव दलितों, मुसलमानों और अति पिछड़े वर्ग समूहों पर पूरी तरह से केंद्रित होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. पार्टी का यह कदम विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए करारा जवाब माना जा रहा है.

वरिष्ठ नेताओं की डिमांड से अटकी है निगम मंडल की सूची

जो नहीं मांग रहे उन्हें अपने आप मिल रहा मौका

भोपाल. मध्य प्रदेश में भले ही सरकार की और 2 आयोग के अध्यक्षों के नाम का एलान कर दिया हो पर दावेदारों के बीच खींचतान के कारण फिलहाल निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम अटक गए है! मध्य प्रदेश बीजेपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संगठन की बजाय नेता खुद संगठन को अपनी पसंद का निगम मंडल बता रहे है.

इसके कारण शीर्ष नेतृत्व असमजंस है. बता दें कि दावेदारों में कई सीनियर नेता है जिनके चलते बीजेपी संगठन के मुखिया खुद तय नहीं कर पा रहे क्या करे! बीजेपी कई नेता अपनी पसंद से पदों की मांग कर रहे है. दावेदार ज्यादा हैं, इसलिए संतुलन बनाना मुश्किल होरहा है जातीय, क्षेत्रीय और गुटीय समीकरणों के हिसाब से संतुलन बनाना भी मुश्किल है.

निगम मंडल के दावेदारों सीनियर नेता निगम मंडल चाहते है. निगम मंडल के बारे में बताया गया तो संगठन की पसंद से पहले उन्होंने अपनी पसंद के निगम मंडल बता दिए जिसके कारण मामला होल्ड पर चला गया. ऐसे नेताओ के लिए बीजेपी संगठन ने दिल्ली के ऊपर निर्णय छोड़ दिया है. नेताओ की डिमांड के बीच बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने उन नेताओ को पद बांटने शुरू जिन्होंने डिमांड नहीं की और संयम दिखया.जो नेता सार्वजनिक रूप से दबाव नहीं बना रहे, संगठन के प्रति संयम दिखा रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है. हाल ही में जारी आयोग की सूची में कई ऐसे नाम सामने आए जिनकी चर्चा पहले ज्यादा नहीं थी लेकिन उन्हें मंत्री दर्जा या महत्वपूर्ण पद देकर एडजस्ट किया गया. यानी शांत रहो, समय आने पर इनाम मिलेगा वाला

एक अनार सौ बीमार

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती कई दावेदारों को लेकर है. इसलिए भी चुनाव में देरी हुई.लंबी फेहरिस्त उन सीनियर विधायकों की है जो मंत्री पद की आस लिए दो साल गुजार चुके हैं. लिहाजा मजबूत दावेदारी के साथ ये भी एक कतार है. उधर 2023 के चुनाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके वे नेता जो संगठन में एडजस्ट नहीं हो पाए अब निगम मंडल की उम्मीद लगाए हैं कि पार्टी यहां तो मौका देगी.

सचदेवा का बढ़ेगा कार्यकाल या मिलेगा नया अध्यक्ष?

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की समाप्ति करीब आने के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष पद की दौड़ तेज हो गई है.

पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा इस पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. नेताओं के एक वर्ग का हालांकि यह भी कहना है कि पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मद्देनजर भाजपा की दिल्ली इकाई के मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दूसरा कार्यकाल मिल सकता है. वीरेंद्र सचदेवा ने मार्च में अध्यक्ष के रूप में तीन साल पूरे कर लिए. बीजेपी के संविधान के अनुसार, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और कोई व्यक्ति लगातार अधिकतम दो कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है.

विशेष | कांग्रेस के लिए गढ़ बचाने की चुनौती

नगर निकाय चुनावों में भाजपा की नजर वापसी पर

शिमला. हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बजते ही सियासी पारा चढ़ गया है. पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद रोचक बनती है. कुल 27 नगर परिषदों में भाजपा समर्थित 14 और कांग्रेस समर्थित 13 अध्यक्ष रहे, जिससे दोनों दलों के बीच सीधी और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. एक-एक सीट का महत्व बढ़ गया है और छोटे अंतर ने चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.

जिलावार स्थिति भी इसी संतुलन को दर्शाती है. कांगड़ा में कांग्रेस 5 और भाजपा 3, मंडी में कांग्रेस 3 और भाजपा

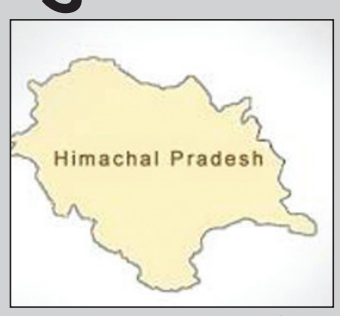

1, सोलन में दोनों परिषद कांग्रेस के पास रहीं, जबकि बिलासपुर में कांग्रेस 2 और भाजपा 1 पर रहीं. कुल्लू में दोनों प्रमुख दलों में 1-1 पर बराबरी की स्थिति रही.

दूसरी ओर सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और चंबा जैसे जिलों में भाजपा का दबदबा साफ नजर आया, जहां अधिकांश या सभी परिषदों पर भाजपा समर्थित अध्यक्ष रहे. मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस सत्ता में है, ऐसे में पार्टी के लिए यह चुनाव अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी है और चुनौती भी. कांगड़ा, मंडी, सोलन और बिलासपुर जैसे जिलों में अपने गढ़ को बचाने के साथ बढ़त बढ़ाने पर फोकस रहेगा. उधर, भाजपा इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मानकर चल रही है. सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और चंबा में मजबूत पकड़ के दम पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहेगी, ताकि आगामी चुनावों के लिए माहौल अपने पक्ष में किया जा सके.

बढ़त बनाने की जुगत- हिमाचल प्रदेश के चार प्रमुख नगर निगमों में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. दो-दो की बराबरी पर चल रहे नगर निगमों में बढ़त बनाने की जुगत में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जुट गए हैं. अब तक पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस समर्थित मेयर, डिप्टी मेयर काबिज थे, जबकि सोलन नगर निगम में कांग्रेस का मेयर और भाजपा का डिप्टी मेयर होने से सत्ता साझा स्थिति में थी. दूसरी ओर धर्मशाला और मंडी नगर निगम पूरी तरह भाजपा के कब्जे में रहे. ऐसे में चारों नगर निगमों में दोनों दलों के बीच संतुलन बना हुआ था.

चारों नगर निगमों में मुकाबला करीबी रहने के आसार

इस बार चुनावों में स्थानीय मुद्दे जैसे शहरों का विकास, सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और ट्रैफिक मुख्य भूमिका निभाएंगे. कांग्रेस जहां अपनी सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखेगी, वहीं भाजपा इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है. चारों नगर निगमों में मुकाबला करीबी रहने के आसार हैं. वार्ड स्तर पर छोटी-सी बढ़त भी पूरे नगर निगम की सत्ता का समीकरण बदल सकती है. हिमाचल के चार नगर निगमों में होने जा रहे चुनाव इस बार केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बनते जा रहे हैं, जहां जीत-हार आने वाले राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगी.